

प्रेषक

मनीषा पवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-01

देहरादून, २९ मार्च 2009

विषय : ग्राम-लखवाड़ (धनपी), विकासखण्ड-कालसी, देहरादून में अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-1381/XVII-1/2005-04(02)/2004, दिनांक 01 दिसम्बर 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम-लखवाड़ (धनपी), विकासखण्ड-कालसी, देहरादून में अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु द्वितीय चिह्नित के रूप में रुपये 40,25,000/- (रुपये पचास लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. आगमन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें 'शिड्यूल ऑफ रेट' में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गईं हो की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षक अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगमन की स्वीकृति मान्य होगी।
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगमन/समवित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाए।
3. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग और "MORTH" द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को समादित कराना सुनिश्चित करें।
4. कार्य कराने से पूर्व स्थल का बर्ती-भाति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार भिर्दों तथा निरीक्षण रिपोर्टों के अनुरूप कार्य किया जाए।
5. आगमन में जिन मदों हेतु जो धनराशि आकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उन्हीं मदों पर किया जाए। एक मद की धनराशि दूसरी मदों में कदापि व्यय न की जाए।
6. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में परीक्षण करा लिया जाए तथा उपर्युक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।
7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2407/XIV-2(9)(2006), दिनांक 30 मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का ऊर्ध्व करत सचय अथवा आगमन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाए।
8. उक्त कार्य स्वीकृत धनराशि से पूर्ण किए जाएंगे। विलम्ब के कारण यदि आगमन का पुनरीक्षण किया जाता है तो कार्यदायी संस्था को अपने निजी स्रोतों से वहन करना होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 एवं 6 में उल्लिखित प्राविधानों एवं वित्तव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. कार्य कराने समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 तथा निविदा विषयक नियमों एवं मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।
11. एकमुस्त प्राकृति को खनने करने से पूर्व विस्तृत आगमन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाए।
12. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाए तथा कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेंसी का होगा।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
14. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चातु वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्यय की 'अनुदान संख्या-31' के 'आयोजनागत कृषि' के लेखाशीर्षक '4225-अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूर्णतः परियोजना-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-277-शिक्षा-01-केन्द्र पोषित/केन्द्र द्वारा पुर्ननिर्धारित योजना-04-अनुसूचित जनजाति छात्रावासों का निर्माण' की मानक मद '24-वृहत निर्माण कार्य' के नामे डाला जाएगा।
15. यह आदेश वित्त विभाग की अस्तसजीव संख्या-864(P)/XXVII(3)/2008-09, दिनांक 12 मार्च 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहे हैं।

भवदीया




(मनीषा पंडेय)
सचिव।

पुष्टांकन संख्या : 29। (1)/XVII-1/2009-04(02)/2004, तददिनांक
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव-माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल ससाधन एवं निर्माण निगम, देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं ससाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
- ✓ 12. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. आदेश पंजीक।

आज्ञा से,



(सी.एम.एस. (विष्ट))
अपर सचिव।